गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) तक आवश्यक सामग्री राज्यों से प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) to (d). The required date has not been received from the States. When received it will be placed on the Table of the House.]

Atrocities on Harijans in States

*223. SHRI JAGJIT SINGH ANAND:†
SHRI F. M. KHAN:
SHRI P. K. KUNJACHEN:
SHRI S. W. DHABE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of incidents involving attacks on Harijans in Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Haryana and Punjab during the period from 1st January to 15th April, 1978 giving number of persons attached, injured, murdered, and the reasons for such attacks, with comparative figures for the corresponding period in 1977 Statewise; and

(b) what action the Central Government have taken or propose to take against persons responsible for such attacks and what measures are proposed to be taken to avoid recurrence of such incidents?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) तथा (ख) राज्यों से आवश्यक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

‡[THE MINSTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). The required data has not been received from the States. When received, it will be placed on the Table of the House.]

SHRI RAMANAND YADAV: Same reply? What can I ask?

MR. CHAIRMAN: I cannot suggest what supplementary you should put.

श्री रामानन्द यादव : श्रीमन्, मंत्री जी को इस प्रश्न को स्थगित करके दूसरे समय में जवाब देना चाहिए था। आपने मुझे सवाल पूछने के लिए कहा है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आए दिन सारे हिन्दुस्तान मे सभी प्रान्तों में हरिजनों पर प्रति दिन अत्याचार होते है। इनके समाचार अखबारों में छपते हैं। शुरू में बेलछी में 11 हरिजन जलाये गये। फिर पथरडीह में हरिजनो की बस्ती में घेरकर उनको स्कूल में लेजाकर बन्द कर दिया गया और तरह तरह के अत्याचार किए गए। धर्मपुरा बिहार राज्य में 4 हरिजनों को दिन में दो बजे गोली से मार दिया गया जमीन के झगडे में जहां हमारे राज्य मंत्री भी गए हुए थे और मैं भी गया हुआ था। फिर बेगूसराय में हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया। कर्ज माफी के कर्ज को वापस न करने पर मधुबनी में हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया। बनारस में और देवरिया में ऐसे ही कांड हुए। आगरा में भी अभी भीषण कांड हुआ।

MR. CHAIRMAN: That is there for discussion today. Therefore, you put your supplementary.

श्री रामानन्द यादव : दक्षिण भारत में एक केस में कोर्ट ने 29 आदमियों को हरिजनों

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagjit Singh Anand.

† [ ] English translation.

पर अत्याचार करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी है इससे यह साफ़ साबित होता है कि देश में हरिजनों पर भीषण रूप से अत्याचार हो रहा है । यही दिल्ली में (*Interruptions*) । होम मिनिस्टर हरिजनों पर अत्याचार के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए यहां मांग की जा रही है कि वह रिजाइन करें । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह पता है कि आये दिन हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं इसके प्रधान कारण क्या हैं ? क्या आर्थिक कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं या सामाजिक कारण हैं ? सरकार स्पष्ट रूप से यह बताये कि ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं और सरकार इनके कारण क्या समझती है ?

श्री धनिक लाल मण्डल : महोदय, माननीय सदस्य ने आये दिन हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके सम्बन्ध में जिन बातों का विवरण दिया है उनके सम्बन्ध के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि बेलछी में जो घटना घटी, बिहार सरकार ने बेलछी की घटना के बाद जो कार्यवाही की उसमें चार पुलिस अफसर मुअत्तिल किये गये । कुल मिलाकर 7 दिनों के अन्दर चार्ज-शीट सबमिट किये गये । जितने लोग मरे थे उनके परिवार वालों को पांच-पांच हजार रुपये दिये गये और उनको जमीनें दी गई हैं।

श्री खुरशीद आलम खान : बड़े दयालु हैं आप ?

श्री धनिक लाल मंडल : माननीय सदस्य ने जो पथरगड़ा की बात कही, पथरगडा में जो हरिजन उजाडे गये, जितने लोगों को उजाडा गया था उनको फिर से बसाया गया है ज़मीन देकर । उनको जमीन दी है । बेगूसराय की बात भी माननीय सदस्य ने कही है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां हरिजनों की मृत्यु नहीं हुई थी । वहां इस तरह की कोई घटना नहीं घटी

(*Interruptions*)

श्री रामानन्द यादव : धर्मपुरा में क्या हुआ ?

श्री धनिक लाल मंडल : धर्मपुरा में जिन चार हरिजनों की मृत्यु हुई उनको प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये दिये गये और उनके परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी दी गई (*Interruptions*) । सात दिन के अन्दर चार्ज शीट भी सब्मिट की गयी । विश्रामपुर जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया, वहां भी जितने हरिजन जले हैं या मरे है . . .

डा० विद्या प्रकाश दत्त : कारण पूछ रहे हैं ।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND (Punjab): Sir...

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Your name is on the list. Why are you worried now?

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने आपको सुना, आप मेरी बात भी सुनिए । विश्रामपुर में जिन लोगों के घर जले है उनको 250–250, 500–500 रुपये मुआवजा दिया गया । जो मरे हैं उन्हें पांच-पांच हजार रुपये दिये गये और उनके परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी दी गई है । सात दिन के अन्दर चार्जशीट सब्मिट की गयी है । 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर कार्यवाही हो रही है सरकार इन मामलों में बहुत ही सतर्क है, सावधान है । इस तरह की जहां भी कोई घटना घटती है उसकी रोकथाम की कोशिश की जाए इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है । प्रधान मंत्री जी ने भी पत्र लिखे । जहां घटना घट जाती है उसके बाद जो कारंवाई होनी चाहिए, सहायता

की कार्रवाई होनी चाहिये, तुरन्त एक्शन की कार्रवाई होनी चाहिये, पुलिस और दूसरे जो लोग दोषी पाये जाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये वे सब काम हो रहे हैं। कारणों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि कुछ जातिगत विद्वेष से होते हैं, सामाजिक कारणों से होते हैं, आर्थिक कारणों से होते है और कुछ जमीन के मामले भी हैं, वेज के मामले भी हैं। मैं यह मानता हूं कि जमीन के मामले भी नोटिस में आए हैं, मजदूरी के मामले भी नोटिस में आए हैं, सामाजिक मामले भी नोटिस में आए है और कुछ व्यक्तिगत विद्वेष के मामले भी नोटिस में आए है।

MR. CHAIRMAN: Let me make one point. There are eight Members on the list. If you are brief, it would be possible to get replies and go further.

श्री रामानन्द यादव : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि हरिजनों पर अत्याचार न हो ? क्या सरकार के पास इसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम है ? क्या सरकार, जो सदन के बाहर और भीतर यह मांग है कि गृह मंत्री इसके लिये जिम्मेवार हैं, उनको रिजाइन कराकर श्री जगजीवन राम को गृह मंत्रालय और उनको डिफेंस मिनिस्ट्री दी जाए, ताकि हरिजनों में कांफिडेंस क्रिएट हो सके, उनकी रक्षा हो सके इस मांग को स्वीकार करने जा रही है ?

श्री धनिक लाल मंडल : मुख्यतः यह राज्य का विषय है। पब्लिक आर्डर का विषय राज्य का विषय है। फिर भी केन्द्रीय सरकार इस विषय पर, हरिजनों के अत्याचार के मामले पर ध्यान रखती है, नजर रखती है। समय-समय पर राज्य सरकारों को पत्र भेजती है, विचार भी देती है और मदद भी देती है।

श्री रामानन्द यादव : आपने जो विचार दिया है वह क्या विचार है ? प्रांतों को जो आपने लिखा है उसको सदन के सामने रखें ताकि हम लोग भी जान सकें।

श्री धनिक लाल मंडल : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि किस तरह से हम कार्रवाई करते हैं। वर्तमान सरकार ने, प्रधान मंत्री ने, जो मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था उसमें इस विषय पर चर्चा की थी। प्रधान मंत्री जी ने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने यह कहा कि डी०एम० और एस०पी० को व्यक्तिगत रूप से इसके लिये जिम्मेवार बनाया जाए। उन्होंने यह भी लिखा कि हरिजनों के अत्याचार के मामले में जो जमीन से सम्बन्धित है इस के लिये कानून में संशोधन लाया जाए और हरिजनों को जमीन से बेदखली करने के मामले को कोग्निजेबुल ऑफेंस माना जाए। गृह मन्त्रीजी ने भी दो अक्तूबर, 1977 को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इन्स्टीट्यूशनल चेंजेंज लाई जाए जिससे जल्दी से जल्दी हरिजनों पर अत्याचार समाप्त हो। उन्होंने जाति के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन चलाने की बात भी कही थी, क्योंकि यही इसका मूल कारण है। मैं ने भी पत्र लिखा था। आप देखेंगे कि जितनी भी यहां से कार्यवाही हुई उसके सन्तोषजनक उत्तर आए हैं। और सभी स्टेटों के होम डिपार्टमेंट्स के अधीन हरिजन सेल खोल दिये गये हैं। ये सैल बड़े अधिकारियों की देखरेख में खोले गये है। जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, वहां पर एक स्पेशियल सेक्रेटरी (होम) के अधीन हरिजन सैल खोला गया है। इसी प्रकार से प्रत्येक जिले में भी हरिजन सैल बना दिये गये है। प्रशासन की तरफ से इस प्रकार के पक्के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि जिससे हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो ही नहीं। हरिजन के ऊपर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए पूरे प्रिवेंटिव मेजर लिये जा रहे हैं। इसके बाद भी अगर घटना घट जाती है तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाती है, इसका संक्षेप में मैने उल्लेख

किया है। इस सम्बन्ध में सब किया जा रहा है और समय आने पर इनका प्रभाव होगा। मेरा विश्वास है और जैसा कि प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि पांच वर्ष में यह समस्या नहीं रह जाएगी।

श्री श्रीकान्त वर्मा : सभापति महोदय, हमारे देश में इस वक्त हरिजनों और आदिवासियों की जो दुरावस्था है उसके लिए हजारों वर्षों के इतिहास को दोष देने की जरूरत नहीं है। इस समय जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए श्री चरण सिंह जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके अनुयायी संगठित होकर अपनी राजनैतिक सत्ता बनाये रखने के लिए हरिजनों पर अत्याचार कर रहे है और इसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं। जहां जहां पर इस प्रकार के अत्याचार हुए है उनमें अनेक पुलिस अफसर शामिल है। ऐसी स्थिति में मैं पहली बात यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ऐसी कोई योजना बनायेंगे कि जो पुलिस अफसर इस प्रकार के अत्याचारों में शामिल होते हैं उनके लिए निर्धारित दण्ड या सजा को बढ़ाया जाएगा? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय राज्य मन्त्री महोदय डा० राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं और डा० लोहिया ने कहा था कि जब तक इस देश में प्रधान मन्त्री कोई हरिजन नहीं हो जाता है तब तक मैं सन्तुष्ट नहीं रहूंगा। ऐसी स्थिति में प्रधान मन्त्री तो कभी न कभी हरिजन होगा ही, लेकिन आज वर्तमान अवस्था में जनता की मांग को देखते हुए क्या हरिजनों और आदिवासियों के लिए आप कोई अलग मन्त्रालय बनाने की व्यवस्था करेंगे?

SHRI MORARJI R. DESAI: I strongly condemn the charge made against the Home Minister that he is responsible or that his followers are responsible for these things. This is a wild charge made here. If it is repeated outside, certainly legal action will be taken against the person concerned.

SHRI BHUPESH GUPTA: On a point of order, Sir.

MR. CHAIRMAN: No point of order.

(Interruptions)

SHRI MORARJI R. DESAI: What I said is that these personal attacks are made here and if they are made outside, then there will be legal action under the defamation law. I did not speak of any other action.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir it is not defamation. It is his fundamental right under article 19 of the Constitution.

(Interruptions)

SHRI MORARJI R. DESAI: I Cannot understand what objection you can have. I am saying that these charges are totally wrong. These charges are totally false and I cannot do anything if they are made here. But if such defamatory charges are made outside, then certainly legal action for defamation will be taken against them by the person concerned.

SHRI BHUPESH GUPTA: I protest against this. It is not defamatory.

SHRI MORARJI R. DESAI: It is for the courts to decide.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is not defamatory.

SHRI MORARJI R. DESAI: That will be for the court to decide, not for you.

(Interruptions)

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, is it parliamentary democracy or Charan Singh democracy?

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am surprised such an experienced parliamentarian saying this....

MR. CHAIRMAN: You are also an experienced parliamentarian.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is open to the citizen to make public charges of this nature against the Ministers and such charges do not make defamation.

MR. CHAIRMAN: That is all right. It is your view.

SHRI MORARJI R. DESAI: He does not know the law at all. I do not want to go into it.

SHRI BHUPESH GUPTA: I do know the law.

SHRI MORARJI R. DESAI: I know what law you know. I have said even earlier that it is not a question of Government having fomented any of these offences. I have said in the other House also that as soon as the Home Minister recovers his health, we want to call a conference of the leaders of all parties so that we can apply our minds to the problem and find out effective remedies to meet the situation.

MR. CHAIRMAN: His supplementary was whether any action will be taken against the police officer who colludes with them.

SHRI SHRIKANT VERMA: Sir, we have great respect for the Prime Minister, not because he is Prime Minister but because he is one of the apostles of the Gandhian philosophy and we expect much more from the Prime Minister and he should not threaten us or he should not intimidate us.

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat. There is only one supplementary he has to reply.

श्री धनिक लाल मण्डल : महोदय, जो हरिजनों पर अत्याचार के मामले होते हैं, उनको स्पेशल केस माना जाता है, ट्रीट किया जाता है और यहां से यह आदेश है, यह इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि डी०एस०पी० और उससे ऊपर के अधिकारी ही उनका इनवेस्टीगेशन करेंगे और जो ड्यूटी में फेल पाये जायेंगे, जो इसके दोषी पाये जायेंगे उनको एडर और अबेटर माना जायेगा। He will be treated as an aider and abettor and dealt with as such.

श्री देवराव पाटील : सभापति जी, यह बात स्पष्ट हो गई है कि केन्द्र तथा विभिन्न हिन्दी भाषी प्रान्तो में जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद हरिजनों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों पर हिंसात्मक अत्याचार बढ़ गये है और इस सिलसिले में जो नान-हरिजन और दूसरे लोग है उनमें खासकर के पुलिस और जो सरकारी अधिकारी है उनका हाथ इन अत्याचारों के पीछे अधिक है और वे इसके लिये उत्तरदायी है। इस सिलसिले में मै एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक दो माह के बालक के विरुद्ध पुलिस ने वारण्ट इश्यू किया है नारायणा गांव में। एक नान-हरिजन जो 4 महीने से लापता था, उसकी हत्या के आरोप में एक हरिजन को पकड़ा और उसकी कोर्ट में पेशी हुई। लेकिन जो व्यक्ति लापता बताया जाता था वह खुद कोर्ट में हाजिर हुआ। इस तरह के अत्याचार पुलिस आफीसरों से हरिजनों पर हो रहे हैं। यह एक षडयन्त्र है और पुलिस वाले जानबूझ-कर हरिजनों के खिलाफ केसेज तैयार करते हैं। इसलिये मैं....

MR. CHAIRMAN: Please be brief.

श्री देवराव पाटील : जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता श्री मोरारजी ने चण्डीगढ़ में कहा कि पांच साल के अन्दर अगर हरिजनों पर अत्याचार बन्द नही हुए

तो हम सत्ता को छोड़ देंगे। उन्होंने ऐसे कई आश्वासन दिये हैं। उस सिलसिले में मैं पूछना चाहता हूं क्या प्रधान मन्त्री महोदय हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके कारणों की समुचित जांच कराने के लिए कोई कमीशन नियुक्त करेंगे ?

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं कि हरिजनों के प्रश्न को पार्टी का प्रश्न न बनाया जाए — यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इसमें एक दूसरे पर आरोप, प्रत्यारोप करके हरिजन समस्या से हाथ सेंकने की कोशिश न की जाए।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Sir, my question was very specific and it did not relate to this year alone. It also asked for the comparatve figures of last year. Now, at least, the figures of last year could be provided. After all, the Government machinery is not so badly damaged after the Janata Government took over that they cannot give these figures. The intention behind the question is to see from the comparative figures whether atrocities on the Harijans are mounting or not. And then, Sir, I am one with the Prime Minister when he says that the atrocities on Harijans should not go in five years but, if it is possible, even earlier. Sir we have nothing against the person of the Home Minister or anybody. But, when atrocities on the Harijans are mounting and when there is a social philosophy to it, to which the Party of the Bharatia Lok Dal was wedded, and the Home Minister is projecting this outlook even today, then naturally the question arises whether the Government will come forward with facts and figures regarding the comparative atrocities and tell us the social causes which, according to me, lie in a reactionary outlook regarding the land reforms. Sir, so long as the Harijans do not have land in villages, they will not have the social status to escape these atrocities. So, Sir, I want to know by when the Government will come forward with these figures. In view of the fact that it is dilly-dallying, will the Government agree to the appointment of a Parliamentary Commission belonging to both the Houses of Parliament comprising Members from all Parties so that this question is taken out of the purview of Opposition and Government tussle and this phenomenon can be curbed, which is destroying the country? At present we hear about incidents like the one in Agra taking place everywhere.

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न में जो सूचना मांगी गई है उसमें मर्डर, आगजनी, आगजनी में घर और फसल और सम्पत्ति के बर्बादी के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है। रेप की सूचना मांगी गई...

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Sir, my question has not been answered. By when will he give us the figures? *(Interruptions)*

श्री धनिक लाल मंडल : जरा सुनिए, बता रहा हूं। इतने कम समय में सूचना नहीं दे सकते है।

MR. CHAIRMAN: Today itself you are going to discuss it. You know it. Why are you worried?

SHRI P. K. KUNJACHEN: Sir, considering the increase in the number at atrocities on Harijans, will the Government think of bringing forward comprehensive legislation for suppressing this oppression on Harijans? Will the Government consider bringing forward comprehensive legislation for that purpose?

श्री धनिक लाल मंडल : कानून तो हैं। केवल उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने की बात है और मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त करने की बात है जिसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

SHRI P. K. KUNJACHEN: Sir, at present the only law which is available to deal with these matters is the Prevention of Untouchability Offences Act. There is no other law to deal with such matters. In the absence of any such thing, there is absolute need to bring forward a comprehensive piece of legislation to deal with these matters. Will the Government think seriously of it?

MR. CHAIRMAN: It is a suggestion.

SHRI S. W. DHABE: Sir, the hon. Minister has just now stated that the law of the land is sufficient to meet the needs of preventing atrocities on the Harijans. But the Home Minister himself has stated that it is not a cognizable offence under the Indian Penal Code. It is a mere trespass and for dispossession of land there is no provision in the Indian Penal Code for stringent punishment. There are one or two provisions prescribing light punishment like six months' imprisonment or something like that. I would like to know from him whether the Home Minister is contemplating taking any preventive action. Is he calling for any monthly reports from the State Governments regarding atrocities on Harijans and other persons, since this trouble has been there for a long time now? Secondly, Sir, I would like to know from the Minister what measures are proposed to be taken by his Ministry for prevention of atrocities on the Harijans.

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, अनटचेबिलिटी आफेंस एक्ट जो अमेंड होकर प्रोटेक्शन आफ सिविल राईट एक्ट आया है उसमें अपराध काग्नीजिबुल है और वह बहुत ही स्ट्रिन्जेंट है। प्रधान मन्त्री जी ने जो चर्चा की है वह जमीन के सम्बन्ध में थी। उन्होंने कहा कि हरिजनों को बेदखल करने के प्रयास को काग्नीजिबुल बनाया जाय, हरिजनों को जो जमीन मिली है या जितनी उनके पास है उनको अगर उस जमीन से बेदखल करने का प्रयास होता है तो इसको काग्नीजिबुल बनाया जाय जिससे कि पुलिस को इन्टरवीन करने का मौका मिल सके।

SHRI S. W. DHABE: What are the preventive measures proposed to be taken?

SHRI DHANIK LAL MANDAL: Sir, the Collectors and the Superintendents of Police are directly responsible for taking effective action. Instructions have been issued to the Chief Ministers of the State Governments. These offences have been made cognizable so that the police can directly intervene in such cases. Immediate steps are being taken for protection of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and for launching a social reform movement. Special police squads to be deployed in the areas where reports of atrocities on Harijans are received.

SHRI KALYAN ROY: He is only reading from the file.

SHRI G. LAKSHMANAN: Mr. Chairman, it is not that atrocities are being committed against the Harijans today. It is from the day of the Aryan invasion over this country that these atrocities began to be committed. Not only that, Sir, these atrocities began from the times the Aryans introduced caste system in this country. It is not that when the Congress was in power, these atrocities were not committed or when the Janata Party took over, the atrocities are being committed. That is the background. No commission can solve this problem: no Act—as my friend said—can solve this problem...

MR. CHAIRMAN: Then?

SHRI G. LAKSHMANAN: We must bring in social reform in this country; we must eradicate the caste system from this country. That is my point. And now I come to my question. Sir,

that was the background to my question. Now, Sir, I find these atrocities are being committed—I am not dividing North and South—only in the northern part of India and these atrocities we find in the northern part only, except Bengal and Assam.

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

SHRI G. LAKSHMANAN: It is not so in South India. I think the Minister will clarify whether it is because of the political changes that have taken place in North India that these atrocities are being committed and because there has been no political change in South India, we do not find these atrocities being committed in South India. Anyhow, I would like to say that these atrocities are being committed only in North India. I would like to know whether the reason is communal or political or economic. I would like to suggest that since these atrocities have been recently reported in 4 or 5 places, a Parliamentary commission should be formed to visit those places where these atrocities have been committed to find out whether these are economic, political or communal in nature. Unless and until Parliament takes up that responsibility, we will not be able to know the reason. We must find out why these atrocities are being committed only in North India and whether it is because there have been no political changes in South India that there have been no atrocities there, and since there have been political changes in the north, these atrocities are committed.

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्णाटक में भी अत्याचार की घटनाएं होती हैं लेकिन....

MR. CHAIRMAN: He has given so many suggestions for your consideration.

SHRI PILOO MODY: It is 60 per cent political, 30 per cent economic and 10 per cent social.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, I hope I am not asking any defamatory question.

MR. CHAIRMAN: You ask the supplementary.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, I am sure the hon. Minister, as the Home Minister of the country, will not take any supplementary directed against him as defamatory. The hon. Home Minister himself, in one of his pronouncements, has said—it is on record—

"A party whose leadership is not inspired by truth, justice or public interest can never deliver the goods or render any service to the people."

This is from Mr. Charan Singh's letter of resignation to Mr. Chandrasekhar. Is it a defamatory statement? It is not a defamatory statement.

MR. CHAIRMAN: You put your supplementary.

SHRI BHUPESH GUPTA: We might say it is devastatingly defamatory of the colleagues of Mr. Charan Singh including Mr. Morarji Desai.

AN HON. MEMBER: What is your supplementary?

SHRI BHUPESH GUPTA: I am coming to my supplementary. Therefore, Sir, I am not going to make defamatory statements. Anyway, I am going by the token of Mr. Charan Singh. How is it that the Home Ministry is not in a position to furnish the facts and figures asked for in these two questions? Notice had been given. They relate to the previous three or four months. Do I understand that the Home Ministry, under Mr. Charan Singh, is so very inactive, inept and incompetent that it does not care even

to secure the reports of rape on the Harijan women and the atrocities committed against them? Why is the Home Ministry not sending proper instructions and taking steps with the State Governments to see that immediately, if necessary, by radio message the reports of such atrocities are sent? Why should, Sir, in Parliament, the hon. Minister ask for more time? Why should he ask for more time when the facts should be at the tip of his fingers? Sir, I do maintain that the Home Ministry is delinquent in the matter of discharge of its responsibility and it is giving an encouragement.... *(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

SHRI BHUPESH GUPTA: Therefore, Sir, I would ask an assurance from the Prime Minister that, in future, we shall be protected against this kind of evasion on the part of the Government even in the matter of furnishing facts.

SHRI PILOO MODY: This is not a supplementary. This is defamatory.

MR. CHAIRMAN: There is no supplementary.

SHRI MORARJI R. DESAI: Bearing the vehemence of the hon. Member in silence is the only effective reply to him.

MR. CHAIRMAN: Your question is: 'why is it that the figures have not been furnished?'. When the hon. Minister says that he wants notice or that he wants time to collect the information, what can you say?

SHRI BHUPESH GUPTA: What can I? What can you do? You have to do something. You have to tell the hon. Minister that the figures should have been ready with him.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, in the existing law, the Social Security Act, 1975, there are two important clauses. One is a penal clause for collective tax on the poulation of the effected area. This is a collective tax penal clause in relation to the atrocities committed on the Harijans. Under the other clause, the officers who are helping the anti-social elements and those who avoid arresting the anti-social elements are to be treated as abetters. These are the two important clauses in the Social Security Act passed in 1975 by the Congress Government. So many cases have been mentioned here in this House previously also. I would like to know from the hon. Minister whether in any of these cases, they had resorted to the use of these two clauses and whether any action has been taken.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: So many kinds of action have been taken. In regard to Belchi and other cases, action has been taken.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I am seeking your protection. I have asked the Minister about the....

MR. CHAIRMAN: It is all right.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: It is a vague answer. If he wants a notice, it can be all right, but here he says . . .

MR. CHAIRMAN: He has replied. Yes, Mr. Jha.

श्री कमल नाथ झा : मेरा एक सवाल है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम ने निर्देश दिया है कि हर जिले के अधिकारी को एस पी को और डी एम को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहराया जायगा। हरिजनों पर अत्याचार अगर होते है तो उन के निर्देश के बाद जो अत्याचार हुए है वह कितने जिलों में हुए हैं, बिहार में या दूसरी जगहों पर और उन में सरकार ने कितने डी एम्स और एस पीज को जिम्मेवार ठहराया है।

श्री धनिक लाल मंडल : हम ने प्रधान मंत्री जी के निर्देश के अनुसार राज्य सरकारों को इस के लिये निर्देशित किया है और जहां जहां इस तरह के अत्याचार हुए हैं वहां के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Enquiry Committee on the Working of the Delhi Transport Corporation

*214. SHRI R. NARASIMHA REDDY:
SHRI KHURSHED ALAM KHAN:
SHRI JAGDISH JOSHI:
SHRI IBRAHIM QALANIYA:

Will the Minister of HIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the scope of the enquiry committee appointed to inquire into the working of the Delhi Transport Corporation is limited to routine operational matters;

(b) whether it is also a fact that quite a few such panels were appointed in the past also; and

(c) whether Government are considering any long term plans for the solution of transport problem of Delhi; if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE INCHARGE OF THE MINISTRY CF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) to (c) A statement giving the information required is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Enquiry Committee on the working of the Delhi Transport Corporation

(a) The terms of reference of the Committee cover questions relating to existing route structure, quality of services rendered by the Corporation to the travelling public, the behaviour of the operating staff, the adequacy of the existing system of public relations, present arrangements for attending to public complaints and grievances in the Corporation, reasons for the present rate of road accidents and working of the DTC Workshops These are, no doubt, operational matters but are important from the point of improvement in the quality of public transport service in Delhi.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir. The DST has prepared a programme for the purchase of 2479 buses comprising 1043 buses for replacement and 1706 buses for additions to the fleet during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1983. An outlay of Rs. 60 crores has been proposed for the Corporation's capital scheme during the above period, including purchase of buses. With the acquisition of these buses and strengthening of the maintenance facilities for buses, resulting in increased availability of buses on road, it is expected that the requirements of the commuters in Delhi will be adequately met.

Unidentified Flying Object

*215. SHRI GOVINDRAO RAMCHANDRA MHAISEKAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an unidentified flying object was reportedly seen recently over Delhi; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE PRIME MINISTTR (SHRI MORARJI R. DESAI): (a) There is